(b) The yearly demand of pulses including Masoor Dal depends on a number of factors like availability of other pulses as well as substitutable foodgrains and foodstuffs, the level of their prices, the level of income of the consumers, population growth, etc. In view of this, it is difficult to frame an estimate of normal consumption requirement of Masoor Dal. It may, however, be stated that during the three year period 1974—76, the average annual quantity of all pulses available for human consumption was 9.7 million tonnes.

Statement

Estimate of production of Masoor dal during 1975-76 and 1974-75 for selected States.

(Thousand tonnes)

State	1975-76	1974-75
Assam .	4·7	5·5
Bihar	88·6	98·3
Haryana .	11·9	11·3
Himachal Pradesh	1·0	1·0
Jammu & Kashmir	0·4	0·4
Madhya Pradesh	156·3	149·5
Maharashtra	5·9	5·1
Punjab	9·0	9·0
Rajasthan	6·5	9·1
Tripura .	0·2	0·1
Uttar Pradesh .	104·2	93·8
West Bengal .	74·0	74·0

Source:-- All India Final Estimates of Rabi pulses (Other than gram and tur) 1975-76.

Shortage of Sugar

5508. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there has been acute shortage of sugar in the country during the years 1975-76 and 1976-77;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the steps taken by Government to check the rise in the price of this commodity?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No, Sir.

(b). Des not arise.

(c) Free-sale sugar prices registered an upward trend during the first half of May, 1977. With a view to bringing down the prices, Government increased the releases of free-sale sugar from 90 thousand tonnes in May, 1977 to 120 thousand tonnes during June and July. The same quantity has now been released for August, 1977 also. This had a salutary effect on the market as sugar prices showed a declining trend in the principal markets in the country which are generally ruling lower by Rs. 5 to Rs. 15 per quintal in most parts of the country at present as compared to those at the end of May, 1977.

उचित दर की दुकानों में नियंत्रित गेहूं चीनी के वितरण में गोलमाल

5509. **श्री युवराज** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों की संख्या 1,86,000 से अधिक है तथा नियंत्रित गेहूं और चीनी के वितरण में भारी घोटाला होता है और अधिकतर जनता को इसकी उचित मूल्य पर आपूर्ति नहीं हो पाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) . इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों, चीनी आदि

का वितरण करने के लिए लगभग 1.87 लाख उचित मूल्य की दुकानें काम कर रही हैं। राज्य के अन्दर खाद्यान्नों और चीनी के वितरण की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। ग्रामीण इलाकों में कुल मिलाकर उचित मूल्य की दुकानें संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं और उन क्षेत्रों के लोगों को गेहूं और चीनी न मिलने के बारे में प्राप्त शिकायत को सम्बन्धित राज्य सरकार को उस पर कार्यवाही करने के लिए भेजा जाता है। सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की अचानक जांच पड़ताल की जानी चाहिए और कसूरवार पाये जाने वाले व्यक्तियों को कठोर सजा दी जानी चाहिये।

ग्रामीण विकास के लिए बैंकों का योगदान

5510. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भी बैंक ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन राशि का योगदान नहीं दे रहा है;

(ख) क्या वर्तमान सरकार की नीति प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने तथा युवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सहकारी सोसायटियां कृषि ऋण की व्यवस्था के लिए मुख्य संस्थागत स्रोत बनी रहीं। सहकारी वर्ष 1974–75 (30 जून, 1975 को समाप्त होने वाले) के दौरान सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों द्वारा दिया गया अल्प तथा मध्यकालीन ऋण क्रमशः 781.00 करोड़ रुपये तथा 118.00 करोड़ रुपये था। आशा है कि वर्ष 1975–76 में यह क्रमशः 870.00 करोड़ रुपए तथा 110.00 करोड़ रुपये हो जाएगा। कृषि के लिए दीर्घकालीन विकास वित्त के क्षेत्र में भूमि विकास बैंक ऋण के प्रावधान के लिए मुख्य स्रोत बने रहे। जबकि सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्ष 1960–61 में दिए गए नए दीर्घकालीन ऋण केवल 12.00 करोड़ रुपये के थे, ये वर्ष 1974–75 में बढ़ कर 181.00 करोड़ रुपए के हो गए और आशा है कि वर्ष 1975–76 में ये ऋण 193.00 करोड़ रुपए के हैं।

किसानों को कृषि ऋण सुलभ करने के लिए वाणिज्यिक बैंक दूसरे अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्थागत स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। 30 जून, 1976 को कृषि कार्यों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सीधी दी गई धन राशि के बकाया 648.43 करोड़ रुपए के थे। यह उत्तरोत्तर रूप से महसूस किया जा रहा है कि कृषि के लिए सीधे ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों में सीमाएं हैं; अतः वे कृषि ऋण को पूरा करने के लिए उत्तरोत्तर सहकारी पद्धति का उपयोग करेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही संस्थाओं का एक नया समूह हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं जहां विद्यमान संस्थागत ढांचा अपर्याप्त है और कृषि विकास के लिए सम्भाव्यता अच्छी है। समाज के कमजोर वर्गों को वित्त सुलभ करने के लिए उनका विशेष उत्तरदायित्व है। मार्च, 1977 तक 47 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं। इनमें से 45 ने उस तारीख तक 13.09 करोड़ रुपए के ऋण दिए और 10.25 करोड़ रुपए के डिपाजिट जुटाए।